RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 152
दि. 30.10.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 में समुद्री नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया

भारत का समुद्री क्षेत्र तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है: प्रधानमंत्री

हमने एक सदी से भी अधिक पुराने औपनिवेशिक नौवहन कानूनों को 21वीं सदी के अनुकूल आधुनिक, भविष्य के अनुकूल कानूनों से बदल दिया है: प्रधानमंत्री मोदी

भारत के बंदरगाह आज विकासशील देशों में सबसे कुशल बंदरगाहों में गिने जाते हैं; कई मायनों में, वे विकसित देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं: प्रधानमंत्री

भारत जहाज निर्माण में नई ऊँचाइयों तक पहुँचने के तेज प्रयास कर रहा है, हमने अब बड़े जहाजों को बुनियादी ढाँचा संपत्ति का दर्जा दे दिया है: प्रधानमंत्री मोदी

भारत के नौवहन क्षेत्र में काम करने और विस्तार करने का यह सही समय है: प्रधानमंत्री

जब वैश्विक समुद्र अशांत होते हैं, तो दुनिया एक स्थिर प्रकाश स्तंभ की खोज करती है, भारत उस भूमिका को मजबूती और स्थिरता के साथ निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है: प्रधानमंत्री मोदी

वैश्विक तनावों, व्यापार व्यवधानों और बदलती आपूर्ति श्रृंखलाओं के बीच, भारत रणनीतिक स्वायत्तता, शांति और समावेशी विकास का प्रतीक है: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 के अवसर पर वैश्विक समुद्री नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित किया और वैश्विक समुद्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन मेंवैश्विक समुद्री नेतृत्व सम्मेलन में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन 2016 में मुंबई में शुरू हुआ था और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अब यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन के रूप में विकसित हो गया है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 85 से अधिक देशों की भागीदारी एक मजबूत संदेश देती है। उन्होंने इस कार्यक्रम में एकत्रित प्रमुख नौवहन प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, नीति निमार्ताओं और नवप्रवर्तकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की उपस्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने छोटे द्वीपीय देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति को भी स्वीकार करते हुए कहा कि उनके सामूहिक दृष्टिकोण ने शिखर सम्मेलन के तालमेल और ऊर्जा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।

श्री मोदी ने इस सम्मेलन में नौवहन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए, इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नौवहन क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की समुद्री क्षमताओं में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों की उपस्थिति उनकी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "21वीं सदी में, भारत का समुद्री क्षेत्र बड़ी तेजी और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है।" श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वर्ष 2025 इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियां भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि भारत का पहला गहरे पानी का अंतरराष्ट्रीय ट्रांस-शिपमेंट हब, विझिंजम पोर्ट, अब चालू है। श्री मोदी ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोत हाल ही में बंदरगाह पर पहुंचा है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में, भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो क्षेत्र संभाला है, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि पहली बार, किसी भारतीय बंदरगाह ने मेगावाट पैमाने की स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन सुविधा शुरू की है और इस उपलब्धि का श्रेय कांडला पोर्ट को जाता है। उन्होंने कहा कि जेएनपीटी में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है, जहां भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल का चरण 2 शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, "इससे टर्मिनल की हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो गई है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बन गया है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत के बंदरगाह बुनियादी ढांचे में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के कारण संभव हुआ है। उन्होंने सिंगापुर के साझेदारों के प्रति उनके योगदान के लिए विशेष आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत ने समुद्री क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "एक सदी से भी ज्यादा पुराने औपनिवेशिक नौवहन कानूनों को 21वीं सदी के अनुकूल आधुनिक और भविष्य के अनुकूल कानूनों से बदल दिया गया है।" उन्होंने यह भी कहा कि ये नए कानून राज्य समुद्री बोर्डों को सशक्त बनाते हैं, सुरक्षा और स्थायित्व को मजबूत करते हैं और बंदरगाह प्रबंधन में डिजिटलीकरण का विस्तार करते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के अंतर्गत भारतीय कानूनों को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप बनाया गया है। इस अनुकूलन ने सुरक्षा मानकों में विश्वास बढ़ाया है, व्यापार करने में आसानी में सुधार किया है और सरकारी हस्तक्षेप को कम किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से हितधारकों और निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तटीय नौवहन अधिनियम व्यापार को सरल बनाने और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अधिनियम भारत के विशाल समुद्र तट के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित करता है। एक राष्ट्र, एक बंदरगाह प्रक्रिया बंदरगाह संबंधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करेगी और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को काफी कम करेगी। श्री मोदी ने इस प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नौवहन क्षेत्र में ये सुधार भारत की एक दशक लंबी सुधार यात्रा का ही एक हिस्सा हैं। पिछले दस-ग्यारह वर्षों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन ऐतिहासिक रहा है। मैरीटाइम इंडिया विजन के अंतर्गत, 150 से अधिक नई पहल शुरू की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख बंदरगाहों पर आधारित इस परिवर्तन ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, जैसे जन धन योजना और आधार से लेकर डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर और पीएम-किसान तक, को पारदर्शिता, दक्षता और लाभों का सीधा वितरण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है।

उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल यात्रा, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से लेकर दो वर्षों के भीतर तीसरे स्थान पर पहुंचने की राह पर, और 2047 तक 30-32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने तक, इसकी आर्थिक प्रगति का अभिन्न हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के विकास की नींव प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति पर टिकी है।

डीपटेक इकोसिस्टम के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि डीपटेक में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां, सेमीकंडक्टर मिशन और भारत के बौद्धिक संपत्ति इकोसिस्टम को मजबूत करना शामिल है।

रक्षा मंत्री 12वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक - प्लस में भाग लेंगे

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 1 नवंबर, 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेंगे। वे 'एडीएमएम-प्लस के 15 वर्षों पर चिंतन और भविष्य की रूपरेखा' विषय पर आयोजित मंच को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, मलेशिया की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर को आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आसियान के सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य आसियान देशों और भारत के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को आगे बढ़ाना है।

दो दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एडीएमएम-प्लस देशों के अपने समकक्षों तथा मलेशिया के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है।

एडीएमएम, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) का सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहयोगात्मक संगठन है। एडीएमएम-प्लस, आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) और इसके आठ संवाद साझेदारों (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है।

भारत 1992 में आसियान का वार्ता साझेदार बना और इसका पहला एडीएमएम-प्लस 12 अक्टूबर, 2010 को वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था। 2017 से, एडीएमएम-प्लस का आयोजन आसियान और प्लस देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है।

एडीएमएम-प्लस के तहत, भारत 2024-2027 चक्र के लिए मलेशिया के साथ आतंकवाद निरोध पर विशेषज्ञ कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है। आसियान-भारत समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण भी 2026 में निर्धारित है।

प्रधानमंत्री ने जापान की प्रधानमंत्री सुश्री साने ताकाइची को बधाई दी; भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सुश्री साने ताकाइची के साथ गर्मजोशीपूर्ण बातचीत की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री सुश्री ताकाइची को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी तथा उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

दोनों नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर विशेष ध्यान देते हुए भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपने साझा विजन पर चर्चा की।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मजबूत भारत-जापान संबंध महत्वपूर्ण हैं।

भारत के तकनीकी भविष्य के लिए विदेश पर निर्भरता कम करना जरूरी: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

विश्व में एक सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाले से आगे बढ़कर, भारत नवाचार के वैश्विक इंजन के तौर पर उभरा है: श्री गोयल

श्री पीयूष गोयल ने वैश्विक उथल-पुथल को ध्यान में रखकर लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और स्वदेशी नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया

श्री पीयूष गोयल ने नवाचार और युवाओं से जुड़ने से प्रेरित एक जीवंत डीपटेक इकोसिस्टम के निर्माण के लिए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज 'भारत के डीपटेक का समय कालः डिजिटल नेतृत्व से तकनीकी संप्रभुता तक'विषय पर आयोजित टीआईईसीओएन दिल्ली-एनसीआर (द इंडस एंटरप्रेन्योर्स) सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस विषय पर जोर दिया कि भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें विकसित करना और प्रमुख इनपुट के लिए कुछ भौगोलिक क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी की भावना केवल भारत में निर्माण, डिजाइन या सेवाएं देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में दीर्घकालिक विकास, संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने से भी संबंधित है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में दुनिया का सिर्फ बैक ऑफिस या सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाला बनने से आगे बढ़कर नवाचार के एक वैश्विक इंजन के रूप में उभरने का संकल्प लिया है, जो भविष्य के लिए नए विचारों, उत्पादों और तकनीकों को प्रेरित करेगा।

श्री गोयल ने हाल के वैश्विक उथल-पुथल से सीखे गए सबक पर सबका ध्यान खींचा और तन्यकशील आपूर्ति श्रृंखलाओं, स्वदेशी नवाचार और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में, कोविड-19 महामारी से शुरू होकर, राष्ट्रों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तन्यकशीलता, आत्मनिर्भरता और आवश्यक आपूर्ति पर नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में कई बार सचेत किया गया है।

मंत्री ने युवा नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को गहन प्रौद्योगिकी से जुड़ने के लिए प्रेरित करने में टीआईई के प्रयासों की सराहना की और इस सम्मेलन को भारत के गहन प्रौद्योगिकी उत्थान का अग्रदूत बताया।

मंत्री जी ने 2014 में डिजिटल इंडिया पहल की शुरूआत का ध्यान करते हुए, बीते दशक में भारत के उल्लेखनीय डिजिटल बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब भारत में लगभग 250 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, जबकि आज, देश में एक बिलियन से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी की शक्ति

'भारत में आजाद हूं, पर घर वापसी चाहूंगी, चुनाव लड़ने से रोका तो कयामत', दिल्ली से शेख हसीन

बांग्लादेश की अपदस्थ (पद से

हटाया हुआ) प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आखिरकार मीडिया के सामने अपनी 'मन की बात' रखी। दिल्ली से अपना पहला इंटरनेशनल मीडिया इंटरव्यू शेख हसीना ने दिया। 78 वर्षीय हसीना ने कहा, 'मैं भारत में आजादी से रह रही हूं, लेकिन सतर्क भी हूं, मेरा परिवार का हिंसक इतिहास मुझे सावधान रखता है।'

उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी 2026 के चुनावों के बाद अगर कोई वैध सरकार बनेगी, तो बांग्लादेश लौटना चाहूंगी।

डीओटी का लक्ष्य- ग्रामीण भारत में 'समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट' को लागू करना

दूरसंचार विभाग (डीओटी) का लक्ष्य- ग्रामीण भारत में डिजिटल खाई पाटने के लिए 'समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट' को लागू करना है

टीसीओई इंडिया ने तीन गांवों में 'समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट'लागू करने के लिए साझेदार संस्थाओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारतनेट-संचालित के जरिए तीन गांवों को नागरिक-केंद्रित सेवाओं से जोड़ा जाएगा

'समृद्धि केंद्र'शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ई-गवर्नेंस सेवाएं गांवों तक पहुंचाएंगे

समझौते का फोकस सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर- ग्रामीण भारत के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

(जीएनएस)।

दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र (टीसीओई) ने तीन अग्रणी कार्यान्वयन भागीदारों - मध्य प्रदेश के अरी और उमरी में डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन (डीईएफ), उत्तर प्रदेश के चौरावाला में आई-नोवेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और आंध्र प्रदेश के नारकोदुरु में कॉर्पस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड - के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते 'समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवा पायलट' को शुरू करने के लिए किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए भौतिक और डिजिटल सेवाओं के सहज एकीकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत को बदलना है।

'समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट'को एक अभिनव फिजिटल (भौतिक + डिजिटल) सेवा मॉडल के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (सीएआरसी) की पाँचवीं रिपोर्ट सौंपी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के 'नागरिक देवो भव' के अभिगम को राज्य में डिजिटल गुड गवर्नेंस के माध्यम से साकार करने की दिशा में GARC की पाँचवीं रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें

- 'एक राज्य -एक पोर्टल' के विजन के साथ 'सरकार नागरिकों के द्वार पर' के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने हेतु तैयार की गई सिफारिशों पर आधारित रिपोर्ट
- सिंगल साइन-ऑन सिस्टम (रसड) के माध्यम से एक ही यूजर आईडी से मिलेंगी नागरिकों को सभी सेवाएँ
- राज्य सरकार की सेवाओं के लिए बार-बार जानकारी देने से मिलेगी मुक्ति, 'एक बार जानकारी दें, अनेक बार लाभ पाएं' का लक्ष्य होगा साकार
- डिजिटल गुजरात 2.0 पोर्टल के माध्यम से शासन प्रणाली को प्रोसेस-सेन्ट्रिक से सिटिजन-सेन्ट्रिक रूप में परिवर्तित कर अधिक संवेदनशील सेवा वितरण लागू करने

की सिफारिश

गांधीनगर, 29 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के 'नागरिक देवो भव'के सिद्धांत को डिजिटल गुड गवर्नेंस के माध्यम से साकार करते हुए, विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में विकसित गुजरात @2047 से एक नया अध्याय रचने का संकल्प व्यक्त किया है।

उल्लेखनीय है कि इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधारों के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (GARC) का गठन किया है।

अब तक इस आयोग ने राज्य सरकार को चार सिफारिश रिपोर्टें सौंपी हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को ऋषफ्ठ द्वारा 12 प्रमुख सिफारिशों के साथ तैयार की गई पाँचवीं रिपोर्ट सौंपी गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ने डिजिटल तकनीक के व्यापक उपयोग के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा विचार देश को दिया है, जिससे नागरिक केंद्रित सेवाएँ सरल, सुगम और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने योग्य बन सकें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई ऋषफ्ठ की पाँचवीं रिपोर्ट में इस विचार के अनुरूप 'वन स्टेट - वन पोर्टल' (एक राज्य - एक पोर्टल) पहल अपनाने की सिफारिश की गई है।

गुड गवर्नेंस के मॉडल स्टेट के रूप में प्रसिद्ध गुजरात में हर नागरिक को एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएँ एक क्लिक पर उपलब्ध कराने तथा 'गवर्नमेंट ऐट द डोरस्टेप ऑफ सिटिजन'के मंत्र को साकार करने की दिशा में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सम्पादकीय

वेतन आयोग के गठन का समय

केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन की वृद्धि के बारे में सिफारिश के लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें आयोग के गठन की घोषणा कर दी। यह आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप देगा। यही नहीं अब आयोग के लिए टर्न ऑफ रिफरेंस का भी निर्धारण कर दिया है, इसलिए ज्यादा समय लगने की आशंका नहीं है। किन्तु यह बात महत्वपूर्ण है कि आयोग को जिन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, उनमें से पहली बात है कि देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता। जबकि दूसरी यह है कि विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। तीसरा गैर- योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार। चौथा सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय असर क्योंकि राज्य सरकारें भी केंद्र की इन्हीं सिफारिशों को अपनाएंगी। पांचवां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और कार्य परिस्थितियों की तुलना।

वेतन आयोग मात्र केंद्रीय सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशन के बारे में ही सिफारिश नहीं करता बल्कि उनकी सेवा शर्तों की समीक्षा करके उनमें बदलाव भी करने की भी सिफारिश करता है। वेतन आयोग प्रायः दस वर्ष बाद लागू किए जाते हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। सरकार को उम्मीद है कि यह वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर देगी। सच तो यह है कि निजीकरण एवं सेवा क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्चुल सिस्टम लागू होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों में कर्मचारियों की संख्या घटी है। यही नहीं पेंशन के मामले में भी पहले जैसी स्थिति नहीं है। पुरानी और नई दो तरह की पेंशनों का वगाकरण हो जाने से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उतना बोझ नहीं पड़ेगा। जितना कि 25 वर्ष पहले वेतन आयोग के नाम पर जहां लोग खुश होते थे और सरकारें आर्थिक बोझ की आशंका मात्र से घबराती थी। असल में वेतन आयोग लागू करना केंद्र सरकारों की मजबूरी थी।

इस वक्त देश के एक ऐसे राज्य में चुनाव हो रहा है, वहां के लोग भी नए वेतन आयोग से प्रभावित होंगे। इसलिए इस 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर यदि किसी राजनीतिक पाटा को आपत्ति हो तो, हैरानी नहीं होनी चाहिए।

इस घोषणा को सरकार या तो चुनाव के बाद करती अथवा बिहार चुनाव के कुछ दिन पहले। इस 8वे वेतन आयोग के घोषणा से वे लोग तो सीधे लाभान्वित होंगे ही जो केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी है, बल्कि वे लोग भी यह दावा करने में आगे रहेंगे जो राजनीति में सत्ता पक्ष के लिए समर्थन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस वेतन आयोग को अवसर देखकर लागू करने की घोषणा की गई है।

यह सच है कि भारत में तो कभी लोकसभा, कभी राज्य विधानसभा, कभी स्थानीय निकायों के चुनाव और उपचुनाव होते ही रहते हैं। इसलिए सरकार की मुश्किल होती है कि लाभकारी योजनाओं या कार्रवाई के फैसले ले कब! लेकिन लोकतंत्र में निष्पक्ष दिखने की ही जितनी कोशिश करता है उसी का मान बढ़ना है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान वेतन आयोग की घोषणा न करके इसकी तिथि आगे-पीछे कर लेनी चाहिए थी।

गांधीनगर स्थित स्पीपा में 'गाइडेड बाई विजन, गवर्न्ड बाई वैल्यूज'विषय पर 'अटल संस्मरण व्याख्यानमाला'के दूसरे सत्र का आयोजन

पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बुद्धिजीवी, कवि, फिलोसॉफर तथा उम्दा राजनेता थे : भारत के पूर्व राजदूत श्री सुजन आर. चिनॉय

गांधीनगर, 29 अक्टूबर:देश के पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समग्र वर्ष के दौरान 'अटल संस्मरण व्याख्यानमाला'का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभाग, सामान्य प्रशासन विभाग अधीनस्थ सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा) द्वारा अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (एएमए) के सहयोग से 28 अक्टबर 2025 को स्पीपा के गांधीनगर स्थित परिसर में 'गाइडेड बाई विजन, गवर्न्ड बाई वैल्यूज'विषय पर 'अटल संस्मरण व्याख्यानमाला'के दूसरे सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) के महानिदेशक तथा भारत के पूर्व राजदूत श्री सुजन आर. चिनॉय ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक विराट व्यक्तित्व था। वे एक बुद्धिजीवी, कवि, फिलोसॉफर तथा उम्दा राजनेता थे। वाजपेयीजी ने सत्ता, पद, संपत्ति तथा राजनीतिक मामलों को अपने दृष्टिकोण पर कभी हावी नहीं होने दिया। भारत के नागरिकों का कल्याण तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व उनकी नीतियों के केन्द्र में थे।

श्री चिनॉय ने कहा कि वाजपेयीजी एक प्रभावशाली वक्ता थे। वे हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सरलता से बोल सकते थे। वाजपेयीजी किसी विचार, नीति या विचारधारा के विरुद्ध नहीं थे और व्यक्तिगत स्तर पर किसी को नाराज नहीं करते थे। ऐसे गुणों के परिणामस्वरूप उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1950 के दशक में श्री वाजपेयी के राजनीतिक जीवन की शुरूआत हुई थी, जो पाँच दशकों से अधिक समय तक चला था। उन्होंने लोकसभा में 10 टर्म के लिए संसद सदस्य के रूप में तथा राज्यसभा में दो टर्म तक सेवाएं दीं। वाजपेयीजी हमेशा भारत से जुड़े मुद्दों व राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में रुचि रखते थे। देश की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता पर उनके मत बहुत ही सुदृढ़ थे।

भारत के पूर्व राजदूत ने जोड़ा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों; विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रयास बहुत ही परिणामदायी थे। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री; दोनों के रूप में वे उत्तम सिद्ध हुए थे, जिसका उदाहरण पाकिस्तान के साथ लाहौर बस यात्रा और करगिल संघर्ष के दौरान नियंत्रण रेखा पार न करने के निर्णयों से देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त; चीन के साथ उनकी मंत्रणा एक महत्वपूर्ण सफलता सिद्ध हुई थी, जिसके फलस्वरूप सिक्किम को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता मिली थी और सीमा विवाद पर मंत्रणा के लिए विशेष प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का प्रारंभ हुआ था। इतना ही नहीं; भारत तथा अमेरिका के बीच शीत युद्ध के बाद की रणनीतिक भागीदारी के निमार्ता के रूप में वाजपेयीजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी।

श्री सुजन आर. चिनॉय ने जोड़ा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के नेतृत्व में वर्ष 2000 से 2005 का कालखंड भारत-चीन के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के मामले में स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता था। इस दौरान लगभग सभी बड़ी भारतीय आईटी, फार्मास्युटिकल जैसी विभिन्न कंपनियाँ चीन में निवेश कर रही थीं। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने वर्ष 2003 में अपनी शंघाई यात्रा के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी पर आयोजित प्रथम परिषद् को संबोधित किया था और भारत-चीन की आईटी कंपनियों के बीच रणनीतिक जुड़ाव का आ'ान किया था।

यहाँ उल्लेखनीय है कि इस 'अटल संस्मरण व्याख्यानमाला'के मुख्य वक्त भारत के पूर्व राजदूत श्री सुजन रमेशचंद्र चिनॉय एक अनुभवी राजनयिक हैं, जिन्होंने पूर्वी एशिया तथा मध्य-पूर्व में मुख्य पोस्टिंग सहित विश्वभर में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में भारत को सेवा दी है। इतना ही नहीं; उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनयी, रणनीतिक मामलों और आर्थिक भागीदारी की अपनी गूढ़ समझ-बूझ के जरिये भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हाल में श्री चिनॉय नई दिल्ली स्थित एमपी-आईडीएसए के महानिदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं, जो रक्षा एवं रणनीतिक मामलों पर भारत के अग्रणी थिंक टैंकों में एक है। श्री चिनॉय राष्ट्रीय सुरक्षा-अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर अमूल्य अंतर्दृष्टि तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

उन्होंने भारत की जी-20 अध्यक्षता के लिए थिंक20 समूह का नेतृत्व किया और पीएमएमएल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तथा भारतीय वैश्विक मामलों की परिषद् की गवर्निंग काउंसिल में सेवा भी दी। श्री चिनॉय ने सीएपीएफ आधुनिकीकरण योजाओं के मध्यावधि मूल्यांकन का अध्यक्ष पद संभाला और ऑपरेशन सिंदूर के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तथा पश्चिम अफ्रीका में सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा बने।

'अटल संस्मरण व्याख्यानमाला'के दूसरे सत्र में सामान्य प्रशासन विभाग तथा स्पीपा के अधिकारी, कर्मचारी, एएमए के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में डिफेंस स्टडीज फैकल्टी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

जीआई टैग वाले इंडी एवं पुलियानकुडी नीबू की पहली हवाई खेप यूनाइटेड किंगडम रवाना

एपीडा ने कर्नाटक और तमिलनाडु के जीआई टैग वाले इंडी एवं पुलियानकुडी नीबू की पहली हवाई खेप यूनाइटेड किंगडम भेजी

एपीडा की सुविधा के तहत इंडी और पुलियानकुडी नीबू की यूके के बाजारों में दस्तक

यूनाइटेड किंगडम को इंडी और पुलियानकुडी नीबू की खेप भारत के जीआई टैग वाले बागवानी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन

(जीएनएस)।

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 28 अक्टूबर, 2025 को भारत के जीआई-टैग वाले कर्नाटक के विजयपुरा से 350 किलोग्राम 'इंडी नीबू' और तमिलनाडु के तेनकासी से 150 किलोग्राम 'पुलियानकुडी नीबू' की पहली हवाई खेप यूनाइटेड किंगडम भेजी। 500 किलोग्राम की यह खेप निर्यात की गई, जो भारत के जीआई-टैग वाले बागवानी उत्पादों के वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

इस खेप को हरी झंडी दिखाने का समारोह कर्नाटक सरकार के बागवानी विभाग, कर्नाटक लाइम बोर्ड, कर्नाटक सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्री वी. दक्षिणामूर्ति, आईएएस, और तमिलनाडु सरकार के बागवानी विभाग की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया। एपीडा के अध्यक्ष, श्री अभिषेक देव ने इस खेप को हरी झंडी दिखाई और पहल की सराहना करते हुए भारत के क्षेत्रीय कृषि-उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के ऐसे प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे स्थानीय किसानों और उत्पादक समूहों को सीधा लाभ मिलता है।

हरी झंडी दिखाने के दौरान, एपीडा अध्यक्ष ने कहा कि जीआई-टैग वाले उत्पाद इंडी नीबू और पुलियानकुडी नीबू का यह निर्यात भारत की अनूठी कृषि विरासत के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करेगा और क्षेत्रीय विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगा।

किसान-उत्पादक समूहों को वैश्विक उपभोक्ताओं से जोड़कर, यह पहल निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि उत्पादकों को ब्रांडिंग और बाजार विविधीकरण के माध्यम से बेहतर आय प्राप्त हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि एपीडा किसानों के लाभ के लिए ऐसी पहलों को बढ़ाने में निर्यातकों और उत्पादकों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

इसके पूर्व श्री वी. दक्षिणामूर्ति, आईएएस ने अपने संबोधन में कहा कि यह निर्यात पहल कर्नाटक की बागवानी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और किसानों की वैश्विक बाजारों तक पहुँच को बढ़ाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। जीआई-टैग वाले इंडी नीबू की सफल खेप राज्य और केंद्रीय एजेंसियों, निर्यातकों और किसान समूहों के बीच मजबूत सहयोग को दशार्ती है।

इंडी नीबू के बारे में

इंडी नीबू, जिसकी खेती मूल रूप से कर्नाटक के विजयपुरा जिले में की जाती है, अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, तेज सुगंध, अधिक रस देने वाले और संतुलित अम्लता के लिए जाना जाता है। इसका विशिष्ट स्वाद और भौगोलिक विशिष्टता इसे इस क्षेत्र की कृषि उत्कृष्टता की एक पहचान बनाते हैं। अपने पाककला संबंधी उपयोगों के अलावा, इस नीबू को पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक प्रथाओं में भी महत्व दिया जाता है, जो कर्नाटक की गहरी जड़ वाली कृषि विरासत को दशार्ता है।

पुलियानकुड़ी नीबू के बारे में

पुलियानकुडी, जिसे अक्सर "तमिलनाडु का नीबू शहर" कहा जाता है, तेनकासी जिले में स्थित है और बड़े पैमाने पर नीबू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पुलियानकुडी नीबू, विशेष रूप से कडयम किस्म, अपने पतले छिलके, तेज अम्लता, उच्च एस्कॉर्बिक एसिड सामग्री (34.3 मिलीग्राम/100 ग्राम) और लगभग 55% रस प्रतिशत की विशेषता के लिए जाना जाता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, यह असाधारण स्वाद और गुणवत्ता प्रदान करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन को सहारा देता है। इस नीबू को आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2025 में अपना जीआई-टैग प्राप्त हुआ, जो इसके विशिष्ट क्षेत्रीय और पोषण संबंधी गुणों को मान्यता देता है।

इंडी और पुलियानकुडी नीबू की यह पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप वैश्विक बाजारों में भारत के क्षेत्रीय रूप से अनूठी, उच्च-गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रमुख कदम का प्रतीक है। यह पहल भारत के जीआई-टैग वाले उत्पादों की वैश्विक पहचान बढ़ाने और बाजार संबंधों को मजबूत करने के एपीडा के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है, जो किसानों और उत्पादक समूहों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं।

चुनाव संबंधी सभी प्रश्नों/शिकायतों के समाधान के लिए सभी आम नागरिक 1950 मतदाता हेल्पलाइन और 'बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ बुक-अ-कॉल' सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं

चुनाव संबंधी सभी प्रश्नों/शिकायतों के समाधान के लिए सभी आम नागरिक 1950 मतदाता हेल्पलाइन और 'बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ बुक-अ-कॉल' सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने नागरिकों के सभी प्रश्नों/शिकायतों के समाधान के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन और सभी 36 राज्यों एवं जिला स्तरीय हेल्पलाइनों को सक्रिय कर दिया है।

राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (एनसीसी) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा। यह टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होता है। कॉल प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती हैं जो नागरिकों और अन्य हितधारकों को चुनावी सेवाओं और प्रश्नों में सहायता प्रदान करते हैं।

चुनाव आयोग ने समय पर और स्थानीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिले को क्रमशः अपना राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। ये केंद्र पूरे वर्ष सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान संचालित होते हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करते हैं।

सभी शिकायतों और प्रश्नों को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) के माध्यम से दर्ज और ट्रैक किया जाता है।

चुनाव आयोग ने 'बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ बुक-अ-कॉल' सुविधा भी शुरू की है, जिसके माध्यम से नागरिक ईसीआईएनईटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से सीधे अपने संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकते हैं।

नागरिक ईसीआईएनईटी ऐप का उपयोग करके चुनाव अधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी सीईओ, डीईओ, ईआरओ को नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करने और 48 घंटों के अंदर उपयोगकताओं के अनुरोधों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

ये सुविधाएं चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए मौजूदा तंत्र के अतिरिक्त हैं। नागरिक ूङ्गेस्र'ल्ल३२@ॅ्रू.ङ्ग५.ल्ल पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

चुनाव आयोग आम मतदाताओं को चुनाव संबंधी सभी जानकारी, फीडबैक, सुझाव और शिकायतों के लिए 'बीएलओ के साथ बुक-अ-कॉल' और समर्पित मतदाता हेल्पलाइन नंबर- 1950 सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उनकी चिंताओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान हो सके।

राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025: नवाचार, समावेशन और बाजार संपर्कों के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों का सशक्तिकरण

आयोजन 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन की योजना के अंतर्गत विशेष उपलब्धियों का जश्न मनाता है

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक किसान भाग लेंगे

(जीएनएस)।

भारतीय कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30-31 अक्टूबर 2025 को एनसीडीसी और एनसीयूआई परिसर, हौज खास, नई दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धियों का उत्सव है और सहयोग, प्रौद्योगिकी एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसान समूहों को और सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है।

दो दिवसीय कार्यक्रम में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक किसान, कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए), क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ) और प्रगतिशील एफपीओ भाग लेंगे। प्रदर्शनी स्टालों के माध्यम से कुल 267 एफपीओ अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे।

इनमें से 57 एफपीओ स्टॉल एनसीडीसी परिसर, हौजखास, नई दिल्ली में प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें कृषि और मूल्यवर्धित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी जो भारतीय कृषि की समृद्ध विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रदर्शनी में अनाज, दालें, बाजरा, मसाले, तिलहन, फल, सब्जियां, शहद, चाय, कॉफी, डेयरी और जैविक उत्पादों के उत्पादन और विपणन में लगे एफपीओ के साथ-साथ प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित वस्तुएं जैसे अचार, जैम, गुड़, हर्बल और प्राकृतिक उत्पाद, मेवे और पारंपरिक हस्तनिर्मित खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए जाएंगे। यह प्रदर्शन "एक भारत - एक कृषि" की भावना को रेखांकित करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों के एफपीओ एक लचीली और बाजार संचालित कृषि-अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं।

एफपीओ समागम 2025 में प्रमुख कृषि विषयों पर तकनीकी सत्रों और पैनल चचाओं की एक श्रृंखला भी शामिल होगी, जिनमें शामिल हैं:

तिलहन उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन

जल उपयोग दक्षता एवं स्थायी सिंचाई पद्धतियाँ (सुश्री अर्चना वर्मा, सहायक सचिव एवं प्रबंध निदेशक, एनडब्ल्यूएम द्वारा)

प्राकृतिक खेती एवं इसके बाजार अवसर (एनएमएनएफ द्वारा आयोजित)

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) - ऋण तक पहुँच एवं अवसंरचना विकास

शहद उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन (एनबीबी के साथ) डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बाजार पहुँच (फ्लिपकार्ट द्वारा सत्र) उर्वरक और कीटनाशक प्रबंधन (एचआईएल द्वारा सत्र)

एगमार्क प्रमाणन प्रक्रिया और लाभ (डीएमआई द्वारा सत्र)

बीज उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन (एनएससी द्वारा सत्र)

व्यावसायिक संबंधों और साझेदारी के लिए क्रेता-विक्रेता संपर्क इन चचाओं के अलावा, इस कार्यक्रम में उच्च प्रदर्शन करने वाले एफपीओ, सीबीबीओ और कार्यान्वयन एजेंसियों को किसान संघटन, व्यावसायिक प्रदर्शन और डिजिटल सक्षमता में उनकी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक समर्पित क्रेता-विक्रेता बैठक किसानों, कृषि-उद्योगों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के बीच सीधे बाजार संपर्क को भी सुगम बनाएगी,

जिससे ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 किसान उद्यमिता का जशन मनाने और इस बात पर प्रकाश डालने के लिए एक ऐतिहासिक मंच के रूप में खड़ा है कि कैसे सामूहिक प्रयास ग्रामीण परिवर्तन, डिजिटल समावेशन और दीर्घकालिक कृषि व्यवसाय विकास को गति दे रहे हैं - जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में किसानों को उत्पादक, प्रदाता और भागीदार के रूप में सशक्त बनाने की सरकार की कल्पना की पुष्टि करता है।

लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड लॉन्च किया गया

- भारत के कोयला और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड लॉन्च किया गया
- कोयला शक्ति एकीकृत और डेटा-संचालित औद्योगिक प्रणालियाँ विकसित करने के एनआईसीडीसी के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दशार्ता है
- यूएलआईपी (ULIP) द्वारा संचालित, एनआईसीडीसी का कोयला शक्ति प्लेटफॉर्म कोयला क्षेत्र के लिए रियल-टाइम निगरानी और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स को सक्षम बनाता है

(जीएनएस)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) ने "कोयला शक्ति" - स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड (एससीएडी) लॉन्च किया है, जो डिजिटल बदलाव और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह प्लेटफॉर्म कोयला मंत्रालय के निदेशों के तहत एनआईसीडीसी द्वारा विकसित किया गया है और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) द्वारा संचालित है।

कोयला शक्ति भारत के कोयला और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्लेटफॉर्म कोयला उत्पादन, परिवहन और खपत की रियल-टाइम निगरानी को सक्षम बनाता है, जिससे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित होती है। इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने किया। डिजिटल इंडिया और लॉजिस्टिक्स आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, कोयला शक्ति, एकीकृत विश्लेषण ढाँचे के माध्यम से कई प्रणालियों को जोड़ने वाले अगली पीढ़ी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एनआईसीडीसी की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करता है। साल 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत शुरू किए गए डिजिटल गेटवे - यूलिप - का लाभ उठाते हुए, यह प्लेटफॉर्म रेलवे, बंदरगाहों, कस्टम्स, कोयला उत्पादकों और बिजली संयंत्रों जैसे लॉजिस्टिक्स नोड्स में सुरक्षित और निर्बाध डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है।

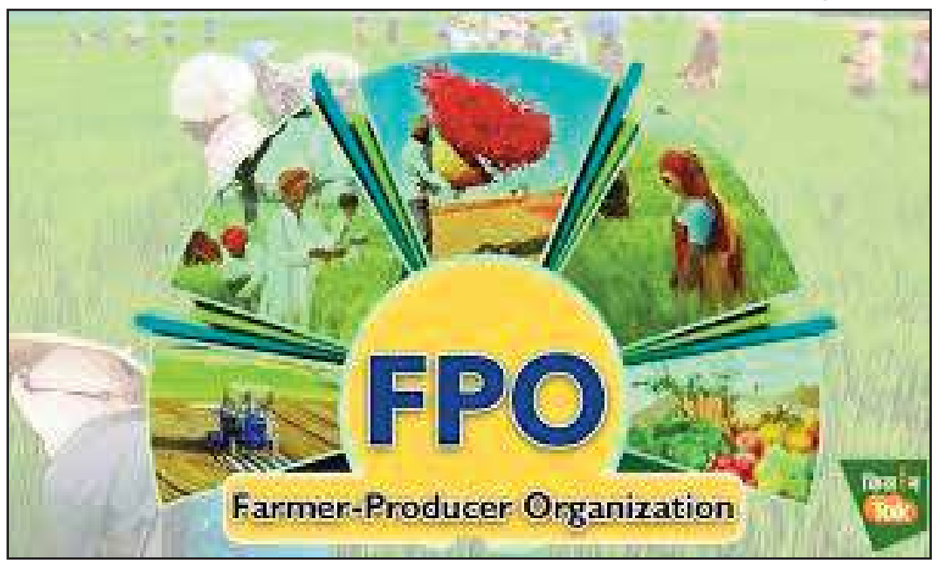

48 से ज्यादा एकीकृत एपीआई और 15 बंदरगाहों से प्राप्त आंकड़ों के साथ कोयला शक्ति, कोयला आपूर्ति श्रृंखला में रीयल-टाइम दृश्यता प्रदान करता है और "एक राष्ट्र, एक डैशबोर्ड" दृष्टिकोण के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित है। यह स्थापना औद्योगिक गलियारा विकास से लेकर राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना और ई-गवर्नेंस तक अपनी विशेषज्ञता को लागू करने में एनआईसीडीसी की सफलता को भी दशार्ती है।

केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य खनन विभागों, बिजली कंपनियों, बंदरगाहों और निजी क्षेत्र सहित प्रमुख हितधारकों के डेटा को एकीकृत करके, यह प्लेटफॉर्म पारंपरिक कोयला लॉजिस्टिक्स को एक बुद्धिमत्तापूर्ण, सक्रिय और स्थायी प्रणाली में बदल देता है। पूवार्नुमानात्मक विश्लेषण और स्थिरता निगरानी उपकरणों का एकीकरण निर्णय लेने और पर्यावरण के प्रति जवाबदेही को और बेहतर बनाता है।

कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, एनआईसीडीसी भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता, लॉजिस्टिक्स दक्षता और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास और पीएम मित्र पार्क जैसी पहलों के प्रबंधन में अपने सिद्ध अनुभव के साथ, निगम अब कोयला शक्ति जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने प्रौद्योगिकीय नेतृत्व का विस्तार कर रहा है, जिससे नवाचार-संचालित विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हो रही है।

इस शुभारंभ समारोह में कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त, एनआईसीडीसी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक श्री रजत कुमार सैनी तथा दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

वडोदरा मंडल पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक ने पारदर्शिता के साथ सिस्टम इंप्रूवमेंट पर दिया बल

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में दिनांक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक " सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी' थीम पर 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह'मनाया जा रहा है। इस संबंध में आज पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल कार्यालय के कांफ्रेंस रूम में सतर्कता जागरूकता पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसे पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन ने सम्बोधित किया। उन्होंने मंडल के अधिकारियों से भारतीय रेल में सेवाओं एवं कार्य में पारदर्शिता के साथ सिस्टम इंप्रूवमेंट पर जोर दिया।

वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन वरिष्ठ सतर्कता अधिकारियों के साथ आज वडोदरा मंडल में वडोदरा पधारे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर मंडल कार्यालय में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन के मार्गदर्शन में तथा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके की अध्यक्षता में सतर्कता जागरूकता मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में

श्री जैन ने विभिन्न विभागों में प्रणाली सुधार के क्रियान्वयन की स्थिति पर मंडल के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।

इस बैठक से पूर्व पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री जैन ने लोको शेड का निरीक्षण भी किया और शेड के अधिकारियों, सुपरवाइजरों एवं कर्मचारियों के साथ सतर्कता विषय पर काउंसलिंग की।

सतर्कता के बारे में जागरूकता के क्रम में प्रातः मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, प्रतापनगर से साइकिल रैली का आयोजन भी किया गया। इस रैली में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन एवं वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया।

यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल की 4 जोड़ी ट्रेनों में लगाए जाएंगे दो-दो अतिरिक्त जनरल कोच

यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल की विभिन्न मार्गों की 4 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से दो-दो अतिरिक्त जनरल सेकंड क्लास (ऋ) कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर, 2025 से 10 नवम्बर, 2025 तक प्रभावी रहेगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-

1. ट्रेन नंबर 19119/19120 वेरावल-गांधीनगर कैपिटल-वेरावल दैनिक एक्सप्रेस
2. ट्रेन नंबर 19207/19208 पोरबंदर-राजकोट-पोरबंदर दैनिक एक्सप्रेस
3. ट्रेन नंबर 59557/59460 भावनगर-पोरबंदर-भावनगर दैनिक पैसेन्जर
4. ट्रेन नंबर 59558/59559 भावनगर-वेरावल-भावनगर दैनिक पैसेन्जर

यह अस्थायी वृद्धि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए की गई है, ताकि सभी यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिल सके।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे सुरक्षित यात्रा करें एवं रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएँ।

बांद्रा टर्मिनस डिपो में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट

मुंबई, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने बांद्रा टर्मिनस डिपो में 100 किलो लीटर प्रतिदिन (केएलडी) क्षमता वाला एक अत्याधुनिक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) स्थापित किया है। यह पहल भारतीय रेल के पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के संकल्प को सशक्त करती है। यह संयंत्र वॉशिंग लाइनों और डिपो गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल के प्रभावी उपचार पर केंद्रित है, जिससे उसके निर्वहन या पुनः उपयोग से पूर्व अपशिष्ट का जिम्मेदार और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह संयंत्र हर महीने 12 लाख लीटर से अधिक अपशिष्ट जल का उपचार करता है और उसे गैर-पेय प्रयोजनों जैसे- कोच धुलाई, प्लेटफॉर्मों और परिसंचरण क्षेत्रों की सफाई, बागवानी और रखरखाव गतिविधियों के लिए उपयुक्त उपचारित जल में परिवर्तित करता है। इस पहल से मीठे पानी की खपत कम होती है, जिससे जल संरक्षण और संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

इस अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और राष्ट्रीय स्वच्छता एवं स्थिरता लक्ष्यों के अनुपालन के प्रति पश्चिम रेलवे की सक्रिय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्नत उपचार तकनीकों को पर्यावरण-संवेदी परिचालन प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करते हुए, पश्चिम रेलवे यह दर्शाती है कि अवसंरचना विकास और पर्यावरणीय दायित्व किस प्रकार संतुलित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, जिससे एक स्वच्छ, हरित और अधिक स्थायी रेलवे नेटवर्क का निर्माण संभव हो पाता है।

31 अक्टूबर से वेरावल-गांधीग्राम के बीच चलेगी दैनिक स्पेशल ट्रेन टिकटों की बुकिंग 30 अक्टूबर (गुरूवार) से होगी शुरू

जूनागढ़ में लगने वाले परिक्रमा मेले के दरमियान होने वाली यात्रियों की भीड़ एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये पर वेरावल-गांधीग्राम के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन ट्रेनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन नंबर 09226 वेरावल-गांधीग्राम दैनिक स्पेशल ट्रेन वेरावल से रात्रि 21.20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 8.00 बजे गांधीग्राम पहुँचेगी। यह ट्रेन 31.10.2025 से 10.11.2025 तक प्रतिदिन चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन नंबर 09225 गांधीग्राम-वेरावल दैनिक स्पेशल ट्रेन गांधीग्राम से रात्रि 22.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 08.45 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन 01.11.2025 से 11.11.2025 तक प्रतिदिन चलेगी।

यह ट्रेन मार्ग में मालीया हाटीना, केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, विरपुर, गोंडल, भक्तिनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर जंक्शन, वढवाण सिटी, बोटाद, धंधुका, धोलका, बावला और सरखेज स्टेशनों पर रूकेगी।

इस ट्रेन में थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे। इस ट्रेन के जनरल कोच और एसएलआरडी कोच अनारक्षित होंगे, जिनके लिए टिकट यूटीएस काउंटर से मिलेंगे तथा इन कोचों में सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस का किराया लगेगा।

ट्रेन नंबर 09226 एवं 09225 के लिए टिकटों की बुकिंग 30.10.2025 (गुरूवार) से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। इन ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएं) संशोधन नियमावली, 2025 अधिसूचित की

चिकित्सा उपकरण नियमों के साथ सामंजस्य से उपभोक्ताओं, उद्योगों और नियामकों को लाभ होगा स्पष्ट घोषणाएं - मजबूत उपभोक्ता विश्वास स्वस्थ भारत के लिए संयोजित मानक पारदर्शी और स्वस्थ भारत की ओर नियामकीय सामंजस्य के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत

(जीएनएस)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। संशोधन में चिकित्सा उपकरणों वाले पैकेजों के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं, जो विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के साथ संयोजित करता है। यह कदम नियामकीय सामंजस्य सुनिश्चित करता है, अनुपालन अस्पष्टता को कम करता है और स्वास्थ्य सेवा सेक्टर में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाता है।

संशोधन में प्रावधान किया गया है कि चिकित्सा उपकरणों वाले पैकेजों के लिए, घोषणाओं में प्रयुक्त अंकों और अक्षरों की ऊंचाई तथा चौड़ाई के लिए चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के प्रावधान लागू होंगे। इसका अर्थ यह है कि अनिवार्य घोषणाएं करने की आवश्यकता तो बनी रहेगी, लेकिन विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों के बजाय चिकित्सा उपकरण नियमों में निर्धारित विशिष्ट फॉन्ट आकार और आयामी मानक लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त, विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमावली, 2011 के नियम 33 के तहत दी गई छूट, जो घोषणाओं में कुछ विशिष्ट रियायत प्रदान करती है, उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 लागू होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विधिक मापविज्ञान के तहत कोई भी छूट केवल इन नियमों के तहत आवश्यक घोषणाओं पर लागू होगी, न कि चिकित्सा उपकरण ढांचे के अंतर्गत आने वाली घोषणाओं पर।

इसके अतिरिक्त, संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सा उपकरणों के लिए विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों के अनुसार प्रिंसिपल डिसप्ले पैनल पर घोषणाएं करना अनिवार्य नहीं है। इसके बजाय, ऐसी घोषणाएं चिकित्सा उपकरण नियमावली 2017 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS
सत्यमेव जयते

यह संशोधन उपभोक्ताओं को चिकित्सा उपकरणों के लिए एकल, सुसंगत लेबलिंग मानक प्रदान करने में सहायक होगा। इससे नियमों के अतिव्यापी होने से उत्पन्न होने वाली उलझनें दूर होंगी और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई स्पष्ट, सटीक और एकसमान लेबलिंग सुनिश्चित होगी। यह विशिष्ट चिकित्सा उपकरण लेबलिंग मानदंडों के साथ संयोजन कर उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करेगा।

इससे उद्योग को भी लाभ होगा क्योंकि इससे दो नियामकीय संरचना के बीच अस्पष्टता दूर होगी, स्पष्टता, पूर्वानुमान सुनिश्चित होगा और नियामक दायित्वों को सुव्यवस्थित करके तथा दोहराव से बचकर व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लेबलिंग मानकों के केवल एक सेट का पालन करने की आवश्यकता के माध्यम से अनुपालन बोझ कम होगा।

विधिक मापविज्ञान प्रवर्तन अधिकारी स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिकार क्षेत्र और प्रयोज्यता के साथ सरल और प्रभावी प्रवर्तन को सक्षम करेंगे। इससे राज्यों और प्रवर्तन एजेंसियों में एक समान व्याख्या और अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

यह सामंजस्य संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा कार्यक्षेत्र में मजबूत उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हुए, व्यवसाय-अनुकूल नियामक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विधिक मापविज्ञान नियमों को चिकित्सा उपकरण नियमों के साथ संयोजित कर यह संशोधन भारत के जीवन-सरलता और व्यवसाय-सुगमता के विजन को आगे बढ़ाता है, जिससे उद्योग के लिए स्पष्टता और उपभोक्ताओं के लिए विश्वास दोनों सुनिश्चित होते हैं।

रक्षा मंत्रालय में 'स्वच्छता विशेष अभियान 5.0'के तहत इलेक्ट्रॉनिक कचरे एवं अनुपयोगी वस्तुओं का निस्तारण

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता विशेष अभियान 5.0 चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न भवनों और परिसरों में ई-वेस्ट तथा अनुपयोगी वस्तुओं के निस्तारण, स्थान के पुनः उपयोग और स्वच्छता को बढ़ावा देना आदि है ।

इस अभियान के तहत मंत्रालय परिसर में रखी अनुपयोगी वस्तुओं एवं ई-वेस्ट का निस्तारण दो चरणों में किया गया। प्रथम चरण में 26 सितंबर 2025 को नीलामी प्रक्रिया में कुल ₹3,50,460 (कर सहित) का राजस्व प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, द्वितीय चरण 3 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया जिसमें नीलामी में ₹3,85,000 (कर सहित) का राजस्व अर्जित हुआ। इस प्रकार दोनों चरणों में कुल ₹7,35,460 (कर सहित) का राजस्व प्राप्त हुआ।

इस अभियान की अवधि के दौरान मंत्रालय के एम-5 साउथ ब्लॉक, सेना भवन तथा कश्मीरी हाउस में रखी अनुपयोगी वस्तुओं का निस्तारण करते हुए लगभग 5600 वर्गफुट स्थान को खाली कराया गया। साथ ही, एम-5 साउथ ब्लॉक स्थित कमरा संख्या एम-5 का रिनोवेशन किया गया, जिससे लगभग 400 वर्ग फुट अतिरिक्त स्थान को कार्यालय उपयोग एवं स्टोर हेतु पुनः उपयोगी हेतु बनाया गया।

इस अभियान के दौरान कार्यालयों और परिसरों में स्वच्छता, सुव्यवस्था और स्थान के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहन मिला। एम-5 साउथ ब्लॉक, सेना भवन और कश्मीरी हाउस में निरंतर की गई सफाई गतिविधियों से कार्यालय के वातावरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

इस अभियान के सफल संचालन में संयुक्त सचिव (स्थापत्य) एवं उनकी टीम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम की शुरूआत में अपर सचिव श्रीमती दीप्ति मोहिल चावला ने सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई एवं स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कोयला शक्ति डैशबोर्ड और सीएलएएमपी पोर्टल का शुभारंभ किया

'कोयला शक्ति' भारत के कोयला इकोसिस्टम की डिजिटल रीढ़ बनेगी- कोयला मंत्री

(जीएनएस)।

डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान (सीएलएएमपी) पोर्टल का शुभारंभ किया। यह आयोजन कोयला क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और डेटा-संचालित शासन की दिशा में मंत्रालय की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।

इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त, अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी श्रीमती रूपिंदर बरार, अपर सचिव श्री सनोज कुमार झा, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के अग्रज और पूरे क्षेत्र के प्रमुख हितधारक उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि कोयला शक्ति डैशबोर्ड का शुभारंभ संपूर्ण कोयला मूल्य श्रृंखला को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह नवोन्मेषी प्रणाली वास्तविक समय समन्वय को मजबूत करेगी, पारदर्शिता बढ़ाएगी और पूरे क्षेत्र में डेटा-संचालित शासन को सक्षम बनाएगी। केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोयला शक्ति भारत के कोयला इकोसिस्टम की डिजिटल रीढ़ के रूप में काम करेगी, जो सरकार के आत्मनिर्भर भारत और "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी।

केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सीएलएएमपी पोर्टल पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के मंत्रालय के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह पोर्टल कोयला-आधारित क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में जवाबदेही बढ़ाने और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिससे न्यायसंगत और समयबद्ध मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित होता है।

कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि कोयला शक्ति डैशबोर्ड और सीएलएएमपी पोर्टल मंत्रालय के सुधारोन्मुखी और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि दोनों प्लेटफॉर्म कोयला मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन मानकों में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि वास्तविक समय डेटा एकीकरण और निर्णय समर्थन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर

मंत्रालय का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, देरी को कम करना और हितधारकों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। श्री दत्त ने पुनः पुष्टि की कि मंत्रालय नीति और प्रक्रिया सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है जो कोयला क्षेत्र को परिचालन उत्कृष्टता के अगले स्तर तक ले जाएगा।

अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी श्रीमती रूपिंदर बरार ने कोयला शक्ति, स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड (एससीएडी) पर केंद्रित एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि पोर्टल की संकल्पना एक एकीकृत, वास्तविक समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है, जो कोयला उत्पादक कंपनियों, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों, रेलवे, बंदरगाहों और बिजली उपयोगिताओं सहित कोयला मूल्य श्रृंखला में कई स्रोतों से डेटा को एकीकृत करता है। यह डैशबोर्ड कोयला उत्पादन, प्रेषण, लॉजिस्टिक्स और खपत पर संपूर्ण दृश्यता प्रदान करता है, जिससे हितधारकों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित होता है।

श्रीमती बरार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोयला शक्ति रेल, सड़क और मल्टीमॉडल प्रणालियों के माध्यम से कोयले की आवाजाही की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम बनाती है, जिससे बेहतर मांग पूर्वानुमान और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण की सुविधा मिलती है। यह प्रणाली प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को एकल, आसानी से नेविगेट करने योग्य इंटरफेस में समेकित करके दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है। उन्होंने संक्षेप में यह भी बताया कि सीएलएएमपी पोर्टल भूमि अधिग्रहण प्रबंधन और अनुपालन प्रक्रियाओं को मजबूत करके कोयला शक्ति का पूरक बनेगा।

कोयला शक्ति डैशबोर्ड के बीच वास्तविक समय समन्वय की सुविधा प्रदान करता है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है और निर्बाध कोयला लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित होता है।

एक व्यापक निर्णय-समर्थन प्रणाली के रूप में, कोयला शक्ति डेटा-संचालित शासन को सक्षम बनाती है, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करती है और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत बनाती है। यह पहल, सरकार के आत्मनिर्भर भारत और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप, पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी नवाचार के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

डैशबोर्ड के बारे में

दशकों से, उत्पादन, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, प्रेषण और खपत को शामिल करने वाली कोयला आपूर्ति श्रृंखला में कई हितधारक और जटिल समन्वय शामिल रहा है। "कोयला शक्ति" वास्तविक समय में पूरे इकोसिस्टम में डेटा को एकीकृत करके इन बाधाओं को दूर करती है।

यह मंच एक व्यापक निर्णय-समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो सुनिश्चित करता हैः

कोयला कम्पनियों, रेलवे, बंदरगाहों और अंतिम उपयोगकताओं के बीच निर्बाध समन्वय।

डेटा-संचालित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही।

लाइव एनालिटिक्स और डिजिटल डैशबोर्ड द्वारा तेज और स्मार्ट निर्णय लेने की क्षमता।

यह एक क्रांतिकारी कदम है जो कोयला क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की सूरत बदल देगा, जिससे बेहतर लॉजिस्टिक्स, कम लागत और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से बिजली, इस्पात और सीमेंट उद्योगों के लिए कोयले की उपलब्धता में अधिक विश्वसनीयता आएगी।

कोयला मंत्रालय का स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड (एससीएडी) कोयला शक्ति एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो कई हितधारकों के डेटा को एकीकृत करता है, जिसमें शामिल हैंः

कोयला उत्पादक कंपनियां और निजी खनिक

केंद्रीय मंत्रालय और विभाग जैसे कोयला, रेलवे, बिजली, वित्त, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग

कोयला उत्पादन का प्रबंधन करने वाले राज्य विभाग (ई-खनिज प्लेटफॉर्म)

बिजली उत्पादन कंपनियां और अन्य औद्योगिक कोयला उपभोक्ता

बंदरगाह प्राधिकरण और निजी कोयला-हैंडलिंग टर्मिनल

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

कोयला शक्ति का प्राथमिक उद्देश्य परिचालन दक्षता को मजबूत करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और कोयला आपूर्ति श्रृंखला में समन्वय को बढ़ाना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैंः

एकीकृत दृश्यताः विविध डेटा स्रोतों का एकल, व्यापक इंटरफेस में एकीकरण।

वास्तविक समय निगरानीः कोयला उत्पादन, प्रेषण और लॉजिस्टिक्स संचालन की निरंतर ट्रैकिंग।

डेटा-संचालित निर्णय लेनाः साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और प्रबंधन निर्णयों का समर्थन करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण।

घटना प्रतिक्रियाः समय पर अलर्ट और सूचनाएं, जिससे परिचालन चुनौतियों का तेजी से समाधान संभव हो सके।

मानकीकरणः विभागों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एकसमान मीट्रिक और रिपोर्टिंग प्रारूप।

परिचालन दक्षताः निगरानी और रिपोर्टिंग का सरलीकरण, मैन्युअल त्रुटियों को न्यूनतम करना।

मापनीयताः भविष्य की डिजिटल प्रणालियों और अतिरिक्त डेटा सेटों के साथ एकीकरण का प्रावधान।

पारदर्शिता और जवाबदेहीः सभी हितधारकों के लिए प्रदर्शन संकेतकों की बेहतर दृश्यता।

नीति नियोजन और पूर्वानुमानः मांग पूर्वानुमान और रणनीतिक योजना का समर्थन करने के लिए विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि।

कोयला शक्ति, शासन सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भारत की क्षमता का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह केवल एक डैशबोर्ड नहीं है; यह कोयला क्षेत्र के परिवर्तन की डिजिटल धड़कन है, जो भारत को एक सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है।

सीएलएएमपी पोर्टल

कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान (सीएलएएमपी) पोर्टल एक एकीकृत डिजिटल समाधान है जिसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। भूमि अभिलेखों के एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करते हुए, यह पोर्टल डेटा एकीकरण सुनिश्चित करता है, जवाबदेही बढ़ाता है और प्रक्रियागत देरी को कम करता है। भूमि विवरण अपलोड करने से लेकर मुआवजे के भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर, सीएलएएमपी पोर्टल कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में भूमि प्रबंधन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाता है।

प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे

यह शिखर सम्मेलन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज द्वारा 150 वर्षों की समाज सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति महोत्सव का हिस्सा है इस शिखर सम्मेलन में भारत और विदेशों में आर्य समाज की इकाइयों के प्रतिनिधि भाग लेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2:45 बजे रोहिणी, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आर्यन सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150 वर्षों की समाज सेवा के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

यह शिखर सम्मेलन भारत और विदेशों में आर्य समाज की इकाइयों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा, जो महर्षि दयानंद के सुधारवादी आदर्शों और संगठन की वैश्विक पहुंच की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को दर्शाता है। इसमें "सेवा के 150 स्वर्णिम वर्ष" शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जो शिक्षा, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक उत्थान में आर्य समाज के योगदान के माध्यम से उसकी परिवर्तनकारी यात्रा को प्रदर्शित करेगी।

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महर्षि दयानंद सरस्वती की सुधारवादी और शैक्षिक विरासत का सम्मान करना, शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण में आर्य समाज की 150 वर्षों की सेवा का जश्न मनाना और विकसित भारत 2047 के अनुरूप वैदिक सिद्धांतों और स्वदेशी मूल्यों के बारे में वैश्विक जागरूकता को प्रेरित करना है।

प्रधानमंत्री 30-31 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री भाग लेंगे

एकता दिवस परेड में 'विविधता में एकता' विषय पर आधारित झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी

परेड के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं: बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता जिसमें विशेष रूप से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के स्वान शामिल होंगे

प्रधानमंत्री एकता नगर में 1,140 करोड़ रुपये से अधिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

परियोजनाओं का फोकस: पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाना, सुगम्यता में सुधार और स्थायित्व संबंधी पहलों का समर्थन

प्रधानमंत्री 'आरंभ 7.0' के समापन पर 100वें फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30-31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 30 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर जाएंगे और शाम लगभग 5:15 बजे वहां ई-बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। शाम लगभग 6:30 बजे, वे एकता नगर में 1,140 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

31 अक्टूबर को सुबह लगभग 8 बजे, प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन होगा। बाद में, करीब 10:45 बजे, वे 'आरंभ 7.0'में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत करेंगे।

पहला दिन - 30 अक्टूबर

प्रधानमंत्री एकता नगर में विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना, सुगम्यता में सुधार लाना और सतत विकास पहलों को बढ़ावा देना है। कुल 1,140 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली ये परियोजनाएं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में इको-टूरिज्म, ग्रीन मोबिलिटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और आदिवासी विकास को बढ़ावा देने के सरकार के विजन को दर्शाती हैं।

जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें राजपीपला में बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय; गरुड़ेश्वर में आतिथ्य जिला (चरण-1); वामन वृक्ष वाटिका; सतपुड़ा सुरक्षा दीवार; ई-बस चार्जिंग डिपो और 25 इलेक्ट्रिक बसें; नर्मदा घाट विस्तार; कौशल्या पथ; एकता द्वार से श्रेष्ठ भारत भवन (चरण-2) तक पैदल मार्ग, स्मार्ट बस स्टॉप (चरण-2), डैम रिप्लिका फाउंटेन, जीएसईसी क्वार्टर आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री भारतीय शाही राज्य संग्रहालय; वीर बालक उद्यान; खेल परिसर; वर्षा वन परियोजना; शूलपनेश्वर घाट के पास जेटी विकास; स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रैवलेटर सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे।

दूसरा दिन - 31 अक्टूबर

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे और सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड का अवलोकन करेंगे।

भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग : सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित

(जीएनएस)।

भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग (आईआरआईजीसी-एम एंड एमटीसी) के सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की 5वीं बैठक 28-29 अक्टूबर, 2025 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ निदेशालय के मुख्य संचालन के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डाइलेव्स्की इगोर निकोलायेविच ने की।

दोनों पक्षों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा में ध्यान केंद्रित किया गया और मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग तंत्र के दायरे में नई पहलों पर विचार किया गया।

कार्य समूह की बैठक रूस के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग के मुख्य निदेशालय के बीच नियमित बातचीत के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित एक मंच है।

नई दिल्ली में 30 अक्टूबर को अपनी तरह की पहली 'आदर्श युवा ग्राम सभा' पहल का राष्ट्रव्यापी शुभारम्भ

(जीएनएस)।

पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली पहल आदर्श युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस) का संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शुभारम्भ करेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल और केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुगार्दास उइके उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम के दौरान आदर्श युवा ग्राम सभा और एमवाईजीएस पोर्टल पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी अनावरण किया जाएगा। ये डिजिटल उपकरण इस पहल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए हैं। यह पहल जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी), एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) और राज्य सरकार के स्कूलों सहित देश भर के 1,000 से अधिक स्कूलों में शुरू की जाएगी। इस अवसर पर पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों और राज्य पंचायती राज विभागों आदि के छात्रों, शिक्षकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित 650 से अधिक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

आदर्श युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस) जनभागीदारी को मजबूत करने और छात्रों को ग्राम सभा सत्रों में शामिल करके सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देने की एक अग्रणी पहल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, इसका उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक उत्तरदायित्व और नेतृत्व क्षमता का विकास करना और पारदर्शिता, जवाबदेही और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध नागरिक तैयार करना है।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक (जेएमएम) के 12वें सत्र में शामिल हुए

श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, भारत ने अपनी न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की शुरूआत की है और सुलभ, समावेशी एवं प्रौद्योगिकी-संचालित न्याय के दृष्टिकोण को अपनाया है

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने न्याय तक पहुंच और व्यापार वृद्धि में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला; ई-लोक अदालत का शुभारंभ, वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से विवादों को सुलझाने तथा व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले कानूनों एवं नियमों के निर्माण की प्राथमिकता पर बल दिया

एससीओ सदस्य देशों ने कानूनी क्षेत्र, एडीआर तंत्र एवं न्याय प्रणालियों के डिजिटलीकरण में सहयोग पर बल दिया

एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक के 12वें सत्र में संयुक्त वक्तव्य पारित किया; कानूनी जानकारी के पारस्परिक आदान-प्रदान एवं एडीआर तंत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 29 अक्टूबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक (जेएमएम) के 12वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले, दिनांक 04.09.2025, 30.09.2025 और 14.10.2025 को तीन विशेषज्ञ कार्य समूह बैठकें आयोजित की गई जिनमें कानूनी मामलों के विभाग, न्याय विभाग, विधायी विभाग और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इन बैठकों का आयोजन सदस्य राज्य रूस द्वारा किया गया जिनमें आज होने वाले जेएमएम बैठक के दौरान हस्ताक्षरित होने वाले संयुक्त वक्तव्य पर विचार-विमर्श किया गया और उसे अंतिम रूप प्रदान किया गया। बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

बैठक में बेलारूस गणराज्य के न्याय मंत्री एवगेनी कोवलेंको, भारत के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल, ईरान इस्लामी गणराज्य के न्याय मंत्री अमीन हुसैन रहीमी, कजाकिस्तान गणराज्य के न्याय मंत्री एर्लान सरसेम्बायेव, चीनी गणराज्य के न्याय मंत्री ही झोंग, किर्गिज गणराज्य के न्याय उप मंत्री एस.टी. यजाकोवा, पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के विधि एवं न्याय मंत्री आजम नजीर तरार, ताजिकिस्तान गणराज्य के न्याय मंत्री एम.के. अशुरियन और उज्बेकिस्तान गणराज्य के न्याय मंत्री ए.डी. ताशकुलोव ने भाग लिया। एससीओ के उप महासचिव खान सोहेल ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया।

एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी के लिए न्याय तक सस्ता एवं सुलभ पहुंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों को रेखांकित किया। पिछले एक दशक से ज्या समय में, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ, श्री मेघवाल ने इस बात पर बल दिया कि भारत ने अपनी न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया है और सुलभ, समावेशी एवं प्रौद्योगिकी-संचालित न्याय के दृष्टिकोण को अपनाया है।

उन्होंने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस संबंध में, उन्होंने विवादों के निपटारे के लिए एक प्रभावी साधन, ई-लोक अदालत के शुभारंभ की भी जानकारी दी, जो प्रौद्योगिकी एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों से मिलकर बना है और देश के नागरिकों को एक तेज, पारदर्शी एवं सुलभ विकल्प प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में गांधीनगर में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड (एपीएम टर्मिनल्स) द्वारा 17 हजार करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के लिए एमओयू

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'समुद्र से समृद्धि'के विजन को साकार करने के लिए गुजरात की एक और पहल

आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास तथा पीपावाव बंदरगाह के क्षमता विस्तार से गुजरात में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को नई दिशा मिलेगी

एमओयू के परिणामस्वरूप पीपावाव पोर्ट के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम से भारत के 'मैरीटाइम गेटवे'के रूप में गुजरात की पहचान अधिक सुदृढ़ होगी

इस प्रोजेक्ट से भविष्य में रोजगार के प्रत्यक्ष व परोक्ष सहित कुल लगभग 25 हजार अवसर सृजित होंगे

गांधीनगर, 29 अक्टूबर:मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'समुद्र से समृद्धि'के विजन को गुजरात में पोर्ट्स सेक्टर के आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इस उद्देश्य से बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा ए. पी. मोलर (एपीएम)-मार्स्क बोर्ड के अध्यक्ष श्री रॉबर्ट मर्स्क उगगला की प्रेरक उपस्थिति में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) तथा गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड (एपीएम टर्मिनल्स) द्वारा 17 हजार करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का एमओयू हुआ।

इस एमओयू का उद्देश्य पीपावाव बंदरगाह की क्षमता के विस्तार से राज्य में अत्याधुनिक विकास द्वारा गुजरात के समुद्री क्षेत्र को और सुदृढ़ करना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस एमओयू की सराहना करते हुए कहा कि पीपावाव पोर्ट्स के विस्तार के फलस्वरूप गुजरात की भारत के 'मैरीटाइम गेटवे'के रूप में स्थापित हुई पहचान और सुदृढ़ होगी।

इतना ही नहीं; यह एमओयू गुजरात में पोर्ट्स नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाकर राज्य के उद्योगों, निर्यातकों एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सशक्त बनाएगा। इस एमओयू से विकास तथा आयात के समय व खर्च; दोनों में कमी आएगी, बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों, वेयरहाउसिंग तथा सप्लाई चेन की सुविधाएँ विकसित होंगी और राज्य की आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि भी होगी।

इस प्रोजेक्ट से भविष्य में रोजगार के प्रत्यक्ष व परोक्ष सहित कुल लगभग 25 हजार नए अवसर सृजित होंगे। रोजगार के ये अवसर स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगे।

इस समझौता ज्ञापन द्वारा पीपावाव बंदरगाह की वर्तमान कंटेनर, बल्क, लिक्विड तथा रो-रो कारगो वहन करने की क्षमता में वृद्धि होने से बंदरगाह का कामकाज अधिक प्रभावशाली एवं तेज बनेगा। इस निवेश के अंतर्गत हैंडलिंग सुविधाओं, आधुनिक कंटेनर टर्मिनल्स, डिजिटल ऑपरेशन सिस्टम्स तथा पर्यावरणोन्मुखी इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।

यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि इस संभावित विस्तार के बाद पीपावाव बंदरगाह गुजरात के समुद्री क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047'के अनुरूप गुजरात के नॉन-मेजर पोर्ट्स की क्षमता वर्ष 2047 तक 3000 एमएमटीपीए करने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

एपीएम टर्मिनल्स - एशिया तथा मध्य एशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव (सीई) श्री जॉन गोल्डनर ने कहा कि यह निवेश योजना केवल पीपावाव पोर्ट के विस्तार के लिए ही नहीं है; बल्कि इससे गुजरात, भारत एवं वैश्विक व्यापार के लिए नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य पीपावाव को विश्व स्तरीय कार्यक्षमता तथा ग्रीन ग्रोथ का मॉडल बनाने के साथ स्थानीय समुदाय के लिए स्थायी समृद्धि का निर्माण करना एवं समुद्री व्यापार में भारत का नेतृत्व अधिक सुदृढ़ करना है।

इस एमओयू हस्ताक्षर अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं जीएमबी के अध्यक्ष श्री एस. एस. राठौड़, बंदरगाह एवं परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री आर. सी. मीणा, जीएमबी की कार्यकारी उपाध्यक्ष सुश्री रेम्या मोहन तथा जीएमबी के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

मार्स्क तथा एपीएम टर्मिनल्स की ओर से ग्रुप चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर रेने पेडरसन, गुजरात पीपावाव पोर्ट के प्रबंध निदेशक श्री गिरीश अग्रवाल तथा भारत, बांगलादेश एवं श्रीलंका क्षेत्र में मार्स्क के लिए लोक नीति एवं नियमनकारी मामलों के प्रमुख श्री विवेक शर्मा भी सहभागी हुए।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में डॉप्लर मौसम रडार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, इससे क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनियों की सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है

बैठक में विशेष रूप से हाल ही में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर मौसम सम्बंधी बुनियादी ढांचे और आपदा तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा की गई

(जीएनएस)।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और राज्य में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश में डॉप्लर मौसम रडार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनियों की सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

हाल ही में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर, मुख्यमंत्री ने राज्य भर में अतिरिक्त डॉप्लर रडार और स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित करने का अनुरोध किया। इससे प्रत्येक जिले, विशेष रूप से आपदा-प्रवण क्षेत्रों में मौसम सम्बंधी चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और आपदा न्यूनीकरण की दिशा में सभी राज्यों के प्रयासों में सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश के मौसम विज्ञान नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में जनता और स्थानीय अधिकारियों तक महत्वपूर्ण मौसम सम्बंधी जानकारी का समय पर प्रसार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के शासन दर्शन का उल्लेख करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 से ही सहकारी संघवाद की भावना को निरंतर बनाए रखा है और क्षेत्र तथा राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना प्रत्येक राज्य के लिए निष्पक्ष और समतापूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण राज्यों की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन उभरती चुनौतियों का तेजी से और प्रभावी ढंग से सामना करने योग्य बनाना है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि डॉप्लर रडार और एडब्ल्यूएस जैसे उन्नत मौसम विज्ञान उपकरण न केवल आपदा तैयारियों में, बल्कि कृषि, जलविद्युत और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों को कवर करने और जन सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस बुनियादी ढांचे के विस्तार में पूर्ण केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया।

इस बैठक में, पहाड़ी राज्य में विकास टिकाऊ और जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच पूवार्नुमान और आपदा प्रबंधन के वैज्ञानिक ढांचे को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता उभरकर समाने आई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मौसम विभाग और राज्य के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ तालमेल से हिमाचल प्रदेश की चरम मौसम सम्बंधी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता और बढ़ेगी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी में ईपीएफ अधिकारियों के लिए 'निवेश एवं जोखिम प्रबंधन' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया

(जीएनएस)।

ईपीएफ अधिकारियों के लिए नई दिल्ली स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस) में आज 'निवेश एवं जोखिम प्रबंधन' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन अकादमी के निदेशक श्री कुमार रोहित ने किया। देशभर से प्रशिक्षण हेतु अकादमी पहुंचे अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री रोहित ने उन्हें सत्रों के दौरान सक्रिय भागीदारी करने और खुले मन से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि निवेश प्रबंधन एवं वित्तीय विवेक पर केंद्रित इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन पीडीयूएनएएसएस की एक समयानुकूल एवं सार्थक पहल है, जिससे अधिकारियों की वित्तीय समझ तथा रणनीतिक निर्णय क्षमता को और सुदृढ़ होगी।

निदेशक श्री कुमार रोहित ने बताया कि इस पहल के प्रेरणास्रोत केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) और पीडीयूएनएएसएस के डीन श्री रमेश कृष्णमूर्ति हैं। उन्हीं की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व दृष्टि के माध्यम से अकादमी के पेशेवर विकास और संस्थागत उत्कृष्टता के निरंतर प्रयासों को दिशा मिलती है। श्री रोहित ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को ईपीएफओ अधिकारियों के क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण व दूरदर्शी पहल बताया। उन्होंने इस अवसर पर श्री विवेकानंद गुप्ता, आरपीएफसी-क्क का उदाहरण देते हुए यह बताया कि उन्हें विश्व बैंक और मिल्केन इंस्टीट्यूट के पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट (पीएफएएम) कार्यक्रम 2025-26 के लिए चुना गया है, जिसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के बेयस बिजनेस स्कूल में किया जा रहा है। यह उपलब्धि ईपीएफओ अधिकारियों की वैश्विक स्तर पर बढ़ती पेशेवर पहचान और क्षमताओं को प्रदर्शित करती है।

आईसीएफएआई बिजनेस स्कूल, हैदराबाद के प्रोफेसर सतीश कुमार इस कार्यक्रम में संसाधन कार्मिक के रूप में आमंत्रित थे। उन्होंने संस्थागत निवेश, पोर्टफोलियो निर्माण, बॉन्ड मूल्यांकन, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत पोर्टफोलियो मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषयों पर कई ज्ञानवर्धक सत्रों का संचालन किया। अपने व्याख्यानों के दौरान प्रोफेसर कुमार ने इस बात पर विशेष बल दिया कि 'यदि किसी परिसंपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तो उसका प्रबंधन भी संभव नहीं है।' उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि मूल्यांकन सभी निवेश निर्णयों का आधार है। प्रोफेसर सतीश कुमार ने प्रतिभागियों को आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के जनक हैरी मार्कोविट्ज तथा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (सीएपीएम) और शार्प रेशियो के लिए प्रसिद्ध विलियम शार्प के योगदानों से भी अवगत कराया, जिन्हें वर्ष 1990 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।

कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक रिजवान उद्दीन, आरपीएफसी-क ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी जिज्ञासा, सक्रिय भागीदारी और विचारशील प्रश्न इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ईपीएफओ मुख्यालय के निवेश एवं छूट प्रभागों के अधिकारियों की एक टीम को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु विशेष रूप से नामित किया गया है। इसके साथ ही, पीडीयूएनएएसएस के अधिकारी एवं संकाय सदस्य तथा देशभर से चुने गए अन्य प्रतिभागी अधिकारी भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी के बारे में जानकारी :

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीयूएनएएसएस) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का प्रमुख प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है।